



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 77]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2002/चैत्र 27, 1924

No. 77]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2002/CHAITRA 27, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2002

सं. टीएएमपी/8/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, संलग्न आदेशानुसार जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के 23 मार्च, 2000 से 30 सितंबर, 2001 की अवधि की दंडस्वरूप ब्याज की वसूली से संबंधित आदेशों के क्रियान्वयन से छूट देने के अनुरोध को अनुमोदित करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/8/2000-सामान्य

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

..... आवेदक

आदेश

(8 अप्रैल 2002 को पारित)

यह मामला जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के 23 मार्च 2000 से 30 सितंबर, 2001 की अवधि की दंड स्वरूप ब्याज की वसूली के संबंध में इस प्राधिकरण के आदेशों के क्रियान्वयन से छूट देने के प्रस्ताव से संबंधित है।

2. समान प्लेडिंग ग्राउंड के सिद्धांत पर जोर देते हुए, इस प्राधिकरण ने पत्तन प्रयोक्ताओं तथा पत्तन न्यासों-दोनों ओर से विलंबित भुगतानों पर दंडस्वरूप ब्याज के भुगतान का निर्धारण करने के संबंध में 4 फरवरी 2000 को एक आदेश पारित किया था। अंतर्निहित सिद्धांत पर जोर देते हुए इस आदेश में बाद में कुछ महापत्तन न्यासों द्वारा किए गए अनुरोधों के मद्देनजर दंडस्वरूप ब्याज की दर और अनुकंपा अवधि को संशोधित करने के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए। इस प्रकार का अंतिम संशोधन भारतीय पत्तन एसोसिएशन के प्रस्ताव पर विचार करके 5 नवंबर, 2001 को किया गया था।

3. इस परिप्रेक्ष्य में जेएनपीटी ने उपर्युक्त प्रस्ताव भेजा है जिसमें उसने निम्नलिखित बातें कही हैं :-

- (i) पत्तन 23 मार्च, 2000 से 30 सितंबर, 2001 तक प्राधिकरण के आदेशों को क्रियान्वित नहीं कर सका ।
- (ii) प्राधिकरण का प्रारंभिक आदेश मिलने पर जेएनपीटी ने आदेश को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयाँ बताईं । परंतु प्राधिकरण ने सभी महापत्तनों को परामर्श दिया कि वे इस मामले पर भारतीय पत्तन एसोसिएशन से बातचीत करें और समान ब्याज दर तथा जिस सीमा के बाद दंड लागू होगा वह समय सीमा अपनाने के बारे में समन्वित दृष्टिकोण तैयार करें ।
- (iii) प्राधिकरण के आदेशों का आशय समान प्लेइंग ग्राउंड उपलब्ध कराना था । 30 सितंबर, 2001 तक जेएनपीटी ने न तो दंडस्वरूप ब्याज वसूल किया और न ही भुगतान किया ।
- (iv) यदि प्राधिकरण के आदेशों को पूर्व प्रभाव से क्रियान्वित करने का निर्णय किया जाता है तो विलंब के मामलों का पता लगाना और प्रयोक्ताओं से देय राशि की वसूली करना मुश्किल होगा । पूरे मामले में भ्रम की स्थिति बन जाएगी और पत्तन प्रयोक्ताओं की ओर से विरोध होगा । ऐसी स्थिति में पूर्व तारीखों से बिल बनाने से कठिनाइयाँ और मुश्किलें आएंगी ।

4 जेएनपीटी ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त स्थिति पर न्यासी बोर्ड ने 22 फरवरी, 2002 को हुई बैठक में विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि प्राधिकरण से बातचीत करके यह अनुरोध किया जाए कि जेएनपीटी को 23 मार्च, 2000 से 30 सितंबर, 2001 तक दंडस्वरूप ब्याज की वसूली के संबंध में आदेशों के क्रियान्वयन से छूट दी जाए ।

5.1 उपर्युक्त आदेश प्राधिकरण ने अपनी सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया था । यह महापत्तन न्यासों की दरों के मान को संशोधित करने का प्रभाव रखता है, और, महापत्तन दरों एवं शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है । उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण का उपर्युक्त आदेश किसी उच्चतर न्यायिक मंच द्वारा रद्द नहीं किया गया है । जेएनपीटी द्वारा आदेश के क्रियान्वयन में पहले बताई गई कठिनाइयों का पूरी तरह समाधान कर दिया गया । ऐसी स्थिति में जेएनपीटी द्वारा इस प्राधिकरण के आदेश को क्रियान्वित न करने के संबंध में पहले अपनाए गए दृष्टिकोण को महापत्तन न्यास अधिनियम में की गई प्रशुल्क निर्धारण व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता ।

5.2 उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि जेएनपीटी आदेश को 1 अक्टूबर, 2001 से पहले ही क्रियान्वित कर चुका है । अब जेएनपीटी द्वारा आदेश को पूर्व प्रभाव से क्रियान्वित करने में व्यक्त समस्याएं वाजिब और स्वीकार्य प्रतीत होती हैं ।

5.3 जैसा कि विभिन्न संबंधित आदेशों में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, दंडस्वरूप ब्याज के निर्धारण का आशय समान प्लेइंग ग्राउंड उपलब्ध कराना और पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले विलंबित भुगतानों और पत्तन न्यास द्वारा की जाने वाली विलंबित राशि वापसी पर ब्याज के भुगतान के मामले में एकरूपता का प्रावधान करना है । दूसरे शब्दों में, पत्तन यदि प्रयोक्ताओं से विलंबित भुगतानों के लिए दंडस्वरूप ब्याज का उपबंध लागू करता है तो उसके द्वारा की जाने वाली विलंबित राशि वापसी पर भी यही शर्त लागू होगी । इस मामले में जेएनपीटी ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर, 2001 तक किसी पर भी दंडस्वरूप ब्याज के उपबंध लागू नहीं किए गए हैं ।

5.4 इस बात को ध्यान में रखकर कि "समान प्लेइंग ग्राउंड" के शासी सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं किया गया है और निर्धारण को पूर्व प्रभाव से लागू करने में आने वाली विधिक एवं लेखांकन समस्याओं को ध्यान में रखकर, यह प्राधिकरण अब जेएनपीटी द्वारा किए गए अनुरोध को मानने के लिए तैयार है ।

6. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त तर्कों तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण जेएनपीटी को 23 मार्च, 2000 से 30 सितंबर, 2001 की अवधि के दंड स्वरूप ब्याज की वसूली से संबंधित आदेशों के क्रियान्वयन से छूट प्रदान करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/TV/143/2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2002

No. TAMP/8/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the request of the Jawaharlal Nehru Port Trust for exemption from implementing the Orders relating to levy of penal interest for the period 23 March, 2000 to 30 September, 2001 as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/8/2000-Genl.

The Jawaharlal Nehru Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 8th day of April 2002)

This case relates to a proposal from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for grant of exemption from implementation of this Authority's Orders relating to levy of penal interest for the period 23 March 2000 to 30 September 2001.

2. Emphasizing the principle of level playing ground, this Authority had passed an Order on 4 February 2000 prescribing payment of penal interest on delayed payments both ways i.e. by Port users as well as by the Port Trusts. Retaining the underlining principle envisaged, this Order was subsequently amended on a few occasions to modify the rate of penal interest and grace period in consideration of the requests made by some of the Major Port Trusts. The last such amendment was made on 5 November 2001 by considering the proposal made by the Indian Ports Association.

3. In this backdrop, the JNPT has forwarded the proposal in reference wherein it has brought out the following points:-

- (i). The Port has not been able to implement the orders of the Authority from 23 March 2000 to 30 September 2001.
- (ii). On receipt of the initial Order of the Authority, the JNPT has expressed its difficulties in implementing the order. The Authority has, however, advised all the Major Ports to take up this matter

with the Indian Port Association to formulate a coordinated view about adoption of a uniform interest rate as also the time limit beyond which the penalty will apply.

- (iii). The intention behind the Order of the Authority was to provide a level playing ground. Till 30 September 2001, the JNPT neither levied nor paid any penal interest.
- (iv). If it is decided to implement the Orders of the Authority retrospectively, it will become difficult to identify the cases where delays occurred and to recover the dues from users. The entire matter will lead to confusion and protests from port users. In the event, retrospective billing will cause hardships and difficulties.

4. The JNPT has also informed that the position mentioned above was considered by its Board of Trustees in its meeting held on 22 February 2002 and it was decided to approach the Authority with the request to exempt the JNPT from the implementation of the Orders for levy of penal interest from 23 March 2000 till 30 September 2001.

5.1 The Order in reference was passed by this Authority exercising its statutory powers. It has the effect of modifying the Scale of Rates of the Major Port Trusts; and, the Major Port Trusts are legally bound to follow the rates and conditionalities prescribed in their Scales of Rates. It is noteworthy that this Authority's Order in reference has not been set aside by any higher judicial forum. The difficulties earlier expressed by the JNPT in implementation of the Order were adequately dealt with and suitable advice was given to the JNPT. That being so, the approach earlier adopted by the JNPT about not implementing this Authority's Order cannot be said to be in conformity with the tariff setting arrangements envisaged in the Major Port Trust Act.

5.2 Notwithstanding the position discussed above, it is noteworthy that the JNPT has already implemented the Order from 1 October 2001. The problems now expressed by the JNPT in implementation of the order retrospectively appear to be genuine and worthy of admission.

5.3 As has already been clarified in various related Orders, the intention behind the prescription of penal interest is to allow a level playing ground and to provide for uniformity in the matter of payment of interest on delayed payments by the Port users as well as delayed refunds made by the Port Trust. In other words, if the Port applies the penal interest provision for delayed payments from users, the same condition shall be applicable to delayed refunds made by it. In the case in hand, the JNPT has clarified that penal interest provisions have not been enforced either way till 30 September 2001.

5.4 Bearing in mind the fact that the governing principle of 'level playing ground' has not been violated, and recognising the legal and accounting difficulties in enforcing the prescription retrospectively, this Authority is inclined to accede to the request now made by the JNPT.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority grants exemption to the JNPT from implementation of the Orders relating to levy of penal interest for the period 23 March 2000 to 30 September 2001.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT III/IV/143/2002/Exty.]

1271 G1/P2-2

